# प्रेस विज्ञप्ति

बजट अनुमान 2009–10 (लेखानुदान)

तथा

वार्षिक योजना 2009–10

वित्त विभाग

राजस्थान सरकार

# वित्त विभाग

## राज्य के वर्ष 2009–10 के बजट के मुख्य बिन्दु

- चालू वित्त वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आयोजना का आकार 14020 करोड़ रूपये से बढ़कर संशोधित अनुमानों में 14925 करोड़ रूपये रहने की सम्भावना है।
- आगामी वित्त वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा 17322 करोड़ रूपये की योजना मंजूर की है जो चालू वर्ष की अनुमोदित योजना से 23.5 प्रतिशत अधिक है। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। परिवर्तित बजट के उपरान्त इसमें ओर भी वृद्धि होगी।
- चालू वर्ष (2008–09) के बजट अनुमानों में बजट आकार 40885 करोड़ रूपये की तुलना में संशोधित अनुमानों में बढ़ कर 43624 करोड़ रूपये।
- अगले वित्त वर्ष 2009–10 हेतु बजट का आकार 48401 करोड़ रूपये।
- चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रूपये एवं आगामी वित्त वर्ष में 27 करोड़ रूपये का बजट अधिशेष अनुमानित।
- चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में, बजट अनुमान 32986 करोड़ रूपये के विरूद्ध 34383 करोड़ रूपये की राजस्व आय अनुमानित की गयी है। आगामी वित्त वर्ष में कुल राजस्व आय 37996 करोड़ रूपये रहने की सम्भावना है।
- चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में, बजट अनुमान 14562 करोड़ रूपये के विरूद्ध 15134 करोड़ रूपये की राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय अनुमानित की गयी है। आगामी वित्त वर्ष में यह आय 16742 करोड़ रूपये रहने की सम्भावना है।
- राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 7.88 तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 7.93 है।
- केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट के अनुसार राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा 9877 करोड़ रूपये के बजट अनुमान के विरूद्ध संशोधित अनुमान में 8997 करोड़ रूपये रहा। आगामी वित्त वर्ष में यह राशि 9618 करोड़ रूपये होगी।

- राज्य का कुल राजस्व व्यय 31803 करोड़ रूपये के बजट अनुमानों के मुकाबले बढ़कर संशोधित अनुमानों में 34666 करोड़ रूपये रहने की सम्भावना। आगामी वित्त वर्ष में यह व्यय 38909 करोड़ रूपये आकलित किया गया है।

- राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु संशोधित अनुमानों में 6241 करोड़ रूपये एवं आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 6928 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- ब्याज भुगतान दायित्व, राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2008–09 के संशोधित अनुमानों में 18.15 प्रतिशत तथा वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों में 18.23 प्रतिशत।

- ब्याज भुगतान दायित्व, राजस्व व्यय का वर्ष 2008–09 के संशोधित अनुमानों में 18 प्रतिशत तथा वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों में 17.8 प्रतिशत।

- वैश्विक आर्थिक मंदी के मध्यनजर भारत सरकार द्वारा ऋण राहत योजना के तहत चालू वर्ष में राजस्व घाटे को समाप्त करने के प्रावधान में शिथिलता देते हुये राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के स्थान पर 3.5 प्रतिशत की सीमा तक रखने की अनुमति दी है।

- चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में 283 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा रहने की सम्भावना। आगामी वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 913 करोड़ रूपये आकलित किया गया है।

- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों हेतु छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के फलस्वरूप राज्य के संवेतन मद में चालू वर्ष में बजट अनुमानों के मुकाबले संशोधित अनुमानों में 1562 करोड़ रूपये तथा आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 2936 करोड़ रूपये की वृद्धि हुयी है। इसी प्रकार पेंशन मद में यह वृद्धि क्रमशः 810 करोड़ रूपये चालू वित्त वर्ष में एवं 743 करोड़ रूपये आगामी वित्त वर्ष में सम्भावित है। चालू वित्त वर्ष एवं आगामी वित्त वर्ष में प्रदर्शित राजस्व घाटा मुख्य रूप से पेंशन एवं संवेतन मद के व्यय में हुयी वृद्धि के फलस्वरूप है।

- चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 5986 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय किये जाने का आकलन किया गया है जो कि अगले वर्ष बढ़कर 6325 करोड़ रूपये होगा।

- राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमानों में 6714 करोड़ रूपये संभावित है जो आगामी वर्ष में बढ़कर 7356 करोड़ रूपये हो सकता है।

# आयोजना विभाग

## राज्य की वार्षिक योजना 2009–10 के प्रमुख बिन्दु

- राजस्थान की वार्षिक योजना 2009–10 के आकार को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय और योजना आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के बीच नई दिल्ली में दिनांक 18.2.2009 को बैठक हुई थी।
- इस बैठक में योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2009–10 के लिए 17,322 करोड़ रू. के योजना आकार का अनुमोदन किया गया है। इस राशि में उपाध्यक्ष, योजना आयोग की और से स्वीकृत एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 110 करोड़ रू. भी सम्मिलित हैं।
- राज्य विधानसभा में वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुमानों में योजना का आकार 17,328.08 करोड़ रू. प्रस्तावित किया गया है। अगले वर्ष योजना व्यय में की गई बढ़ोतरी से विकास कार्यों को और गति मिलेगी जिससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ लेते हुए विकास कार्यों पर  व्यय में बढ़ोतरी से ही आर्थिक मंदी से निपटा जा सकेगा।
- राज्य की अगले वित्तीय वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना अब तक की सबसे बडी वार्षिक योजना है। राज्य की वार्षिक योजना 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 का अनुमोदित मूल योजना आकार क्रमशः 6,797.50 करोड़ रू., 8,350.00 करोड़ रू., 8,501.42 करोड़ रू., 11,638.86 करोड़ रू. एवं 14,020 करोड़ रू. था।
- अगले वर्ष की वार्षिक योजना चालू वर्ष की वार्षिक योजना के अनुमोदित मूल योजना आकार से 3,302 करोड़ रू. अधिक है। योजना आकार में हुई यह वृद्वि 23.55 प्रतिशत है।
- राजस्थान के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने नीतिगत दस्तावेज के अनुसार पुनर्निधारित की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की वार्षिक योजना 2009–10 का प्रारूप तैयार किया गया है।
- गरीब परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा नैट उपलब्ध कराने के क्रम में मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत गम्भीर रोगों के उपचार एवं शल्य चिकित्सा पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। गरीब, कमजोर वर्गों तथा आम आदमी के लिये वर्तमान में चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों को नई प्राथमिकताओं के अनुसार लागू किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा Economic Stimulus Measures में बढायी गई योजना राशि के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक कदम उठा लिये हैं। समाज के सभी तबकों विशेषतः कमजोर एवं गरीब तबकों को इससे बड़ी सहायता मिलेगी।

- राज्य सरकार द्वारा सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए वार्षिक योजना 2009–10 में राज्यांश की समूचित राशि का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए 267.44 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़, मिड–डे मील के लिए 95 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 670 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशनके लिए 124 करोड़, इन्दिरा आवास योजना के लिए 86.60 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 350 करोड़, एवं एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 235.98 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को आगामी वर्ष में भारत सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की सम्भावना है।
- राजस्थान की वार्षिक योजना 2009–10 में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवासन, नगरीय विकास, समाज कल्याण, जनजाति विकास सम्बन्धी योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये चालू वर्ष के आउटले रुपये 4,271.30 करोड रुपये को बढाकर 5,507.96 करोड रुपये कर दिया है जो कि चालू वर्ष के मूल बजट प्रावधान से 1,236.66 करोड रुपये अधिक है।
- ऊर्जा क्षेत्र हेतु चालू वर्ष के लिये प्रावधान रुपये 6,211.55 करोड को अगले वर्ष बढाकर 7,653.97 करोड रुपये किया गया है।
- ऊर्जा और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के पश्चात् क्रमशः ग्रामीण विकास, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि एवं सहायक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- सिंचाई एवं सिंचित क्षेत्र विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिये अगले वर्ष 963 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- कृषि एवं सहायक सेवाओं के लिये चालू वर्ष के मूल बजट आउटले रुपये 618.79 करोड को बढाकर 845.52 करोड रुपये कर दिया गया है।
- राज्य सरकार ने 660 MW की चार नई बिजली इकाईयां छबडा और सूरतगढ के लिये स्वीकृत कर दी है। वर्ष 2011–12 तक 6,702 मेगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता को बढाकर 12,400 मेगावाट करने का लक्ष्य है। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्राथमिकता दी जायेगी।
- राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के लिये मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की परिवर्तित योजना लागू की गई।
- पूर्ण संस्थागत प्रसव के लिये मार्च, 2009 तक 70 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।